भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 104

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ,1947 (शक) को दिया जाना है।)

नागरिकों के ऋण में वृद्धि

104. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों में सामान्य भारतीय नागरिक के औसत ऋण में 90,000 रुपये की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश का विदेशी ऋण 736.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के ऋण से 10% अधिक है;

(ग) क्या सरकार इस चिंता को स्वीकार करती है कि आर्थिक ऋणों का वर्तमान मॉडल परिवारों को सतत विकास और आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के बजाय जीवन-निर्वाह-आधारित ऋण के चक्र में धकेल सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नागरिक ऋण, आय में कम वृद्धि और बढ़ते विदेशी ऋण की उक्त खतरनाक प्रवृत्तियों को उलटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क), (ग) और (घ): जी नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मार्च 2025 के अंत तक, ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा लगभग—एक ऋण सूचना कंपनी—28 करोड़ विशिष्ट व्यक्तिगत ऋणकर्ता सूचित किये गए थे , जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है। इस विशिष्ट ऋणकर्ता समूह के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025 में यह सूचित किया है कि प्रति व्यक्ति ऋण)जिसके परोक्षी के रूप में व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए उपभोक्ता सेग्मेंट ऋणों को इस्तेमाल किया गया है (मार्च2023 में ₹3.9 लाख से बढ़कर मार्च 2025 में ₹4.8 लाख हो गया है। इस प्रकार, यह डेटा किसी भारतीय नागरिक के औसत ऋण को निरूपित नहीं करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित घरेलू ऋण संबंधी विस्तृत आँकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू ऋण में वृद्धि औसत ऋणग्रस्तता में वृद्धि के बजाय उधारकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण है। इसके अलावा, लगभग दो-तिहाई ऋण उच्च क्रेडिट स्कोर वाले उधारकर्ताओं के हैं। उच्च रेटिंग वाले उधारकर्ताओं का प्रति व्यक्ति ऋण, जिसका उपयोग आमतौर पर परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया जाता है, में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में परिवारों की वित्तीय परिसंपत्तियों का स्टॉक मार्च 2023 में 103.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 106.2 प्रतिशत हो गया। यह परिवारों की निवल वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत देता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध जानकारी के आधार पर, भारत की जनसंख्या से विभाजित, परिवारों की कुल वित्तीय देनदारियाँ (सहकारी बैंकों, बीमा निगमों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सरकार से लिए गए ऋणों सहित), 2022-23 में ₹11545 से बढ़कर 2023-24 में ₹13470 हो गईं, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान केवल ₹1925 की वृद्धि हुई।

(ख): भारतीय रिज़र्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 तक भारत का विदेशी ऋण 736.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2024 की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ङ): सरकार का व्यवसाय सुगमता, कौशल विकास, रोज़गार सृजन और अवसंरचना के निर्माण पर बल देने से आय वृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, ब्याज दरों और नकदी में निरंतर ढील से विकास को बढ़ावा मिलने और परिवारों पर ऋण भुगतान का बोझ कम होने की उम्मीद है। ₹12-12.75 लाख तक की वार्षिक आय पर नई आयकर छूट से मध्यम वर्ग की प्रयोज्य आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे परिवारों को ऋण प्रबंधन और उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। विनियामक दृष्टिकोण से, आरबीआई ने नवंबर 2023 में उपभोक्ता ऋण और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण के कुछ क्षेत्रों पर जोखिम भार बढ़ा दिया था, क्योंकि इन क्षेत्रों में उच्च वृद्धि देखी गई थी। परिणामस्वरूप, असुरक्षित खुदरा ऋण क्षेत्र में ऋण वृद्धि (सीएजीआर) सितंबर 2021-23 के बीच 27.0 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2023- मार्च 2025 के बीच 11.6 प्रतिशत हो गई है।

विदेशी उधारी के संबंध में, भारत अपने बाह्य ऋण का प्रबंधन उल्लेखनीय विवेक के साथ कर रहा है, जैसा कि मार्च 2025 तक 19.1 प्रतिशत के निम्न बाह्य ऋण-से-जीडीपी अनुपात से परिलक्षित होता है। सरकार ने 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करने का प्रस्ताव देकर सार्वजनिक उधारी में वृद्धि को नियंत्रित करने का एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया है और 2031 तक कुल सरकारी ऋण को जीडीपी के लगभग 50% तक लाने का इरादा रखती है, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए बेंचमार्क दरों या ऋण सेवा दबाव में वृद्धि नहीं होगी।

***